रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष अर्थात् 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय आय की वास्तविक दर क्या थी;

(ग) चालू वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय का क्या लक्ष्य नियत किया गया है और क्या यह सच है कि 1987-88 के वर्ष की राष्ट्रीय आय पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम थी; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय के वर्षवार आंकड़े क्या है और चालू वित्तीय वर्ष में इसके कितनी होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो केलेरियो): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1987-88 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि 1987-88 में वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर लगभग 2.5 प्रतिशत होने की आशा है।

(ख) राष्ट्रीय आय के सरकारी अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध त्वरित अनुमान वर्ष 1986-87 से संबंधित है और ये सकल घरेलू उत्पाद (उत्पादन लागत पर) में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 1987-88 के संबंध में अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आय का लक्ष्य वृद्धि दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है न कि वास्तविक अभिहित मूल्यों के अनुसार। सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (उत्पादन लागत पर) में 5 प्रतिशत के औसत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। यद्यपि 1987-88 के संबंध में राष्ट्रीय आय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, व्यापक बहत-आर्थिक प्रवृत्तियों से यह संकेत मिलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1987-88 में इसके अधिक होने की सम्भावना है। चालू वर्ष की राष्ट्रीय आय के सम्भावित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय आय के वर्षवार आंकड़े बाद के तीन वर्षों अर्थात् 1984-85 से 1986-87 तक के उपलब्ध हैं, (1980-81 की कीमतों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद), जो निम्न प्रकार है:—

1984-85 . . 148955 करोड़ रुपए

1985-86 . . 156083 करोड़ रुपए

1986-87 . . 162326 करोड़ रुपए

(त्वरित अनुमान)

"Pollution caused by Public Sector Industrial Units in Uttar Pradesh"

*114. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether the Central Government are aware that some public sector industrial units in Uttar Pradesh are causing environmental pollution; and

(b) if so, what are the details thereof and what steps the Central Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the table of the House. (*See* below)

.. .. **Statement**

A total of 152 public sector undertakings including cooperatives in Uttar Pradesh have been identified by the Uttar Pradesh Pollution Control Board as causing environmental pollution. The steps taken include the following:

(i) Ten out of thirteen Central and State Sector undertakings dis-

charging effluents into the river Ganga have been directed by the Central Government to instal effluent treatment facilities according to a time-bound programme. Two units have been directed to close down and one has been issued a notice for closure.

(ii) The Uttar Pradesh State Pollution Control Board has refused consent in 18 cases under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

(iii) Prosecutions have been launched against 22 public sector undertakings under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

(iv) Industries have been directed to put up effluent treatment facilities.

Rise in Wholesale Price Index

*115. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that official wholesale price index for all commodities (base 1970-71) touched 441 points in October, 1988; and

(b) if so, what are the factors responsible for such rise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Yes, Sir. The Wholesale Price Index (Base 1970-71 -100) for the week ending 15.10.1988 stood at 441.0. However, the index declined to 438.4 as on week ending 29th October, 1988 (latest available). At this level the increase in the index during the current financial year works out to 4.8 per cent which is only about half the increase of 8.8 per cent in the corresponding period of last year. This increase in the index is mainly due to normal seasonal factors.

ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

*116. **श्री शरद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे क्या-क्या उद्देश्य थे और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सके हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो तो ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण बैंकों को निरन्तर घाटा हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो ग्रामीण बैंकों की स्थापना के बाद से यह घाटा कितना हुआ है?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों को कम लागत पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था। जून 1988 के अन्त तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 13568 शाखाएं खोली हैं। इनमें से 12491 शाखाएं अर्थात् लगभग 92 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण केन्द्रों में स्थित हैं। दिसम्बर 1987 के अन्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विभिन्न शाखाओं की जमाराशियां 2306 करोड़ रुपए और अग्रिमों की बकाया राशियां 2232 करोड़ रुपए थीं। इस प्रकार प्रति जमा खाता औसत 1027 रुपए और